DR. KANWAR DEEP SINGH: Sir, my main question was. ...*(Interruptions)*...

श्री सतीश चन्द्र मिश्राः सर, इस इश्यू पर आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए।

श्री सभापतिः आप नोटिस दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सतीश चन्द्र मिश्राः आप इस पर आधे घंटे की चर्चा करवाइए। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: They are agreeing to it. ...*(Interruptions)*... Government is agreeing to it. ...*(Interruptions)*... No problem. ...*(Interruptions)*...

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: When there is no prohibition, why no reservation? ...*(Interruptions)*...

श्री सभापतिः आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI V. HANUMANTHA RAO: Sir, I am asking on the issue of reservation. ...*(Interruptions)*... This is a serious issue, Sir. ...*(Interruptions)*... There should be one hour discussion. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Yes, Dr. Kanwar Deep Singh.

Decreasing land area under cultivation

*137.DR. KANWAR DEEP SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the area of land under cultivation is decreasing; and

(b) if so, the rate of decrease during the last three years?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI RADHA MOHAN SINGH): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) As per report on Land Use Statistics for 2012-13 (latest available), total land under cultivation/cultivable land in the country has marginally declined from 182.01 million hectares in 2010-11 to 181.96 million hectares in 2011-12 and further to 181.95 million hectares in 2012-13. The average decrease in the cultivable land in the country during the above period has been 0.03 million hectares per year.

DR. KANWAR DEEP SINGH: Sir, my main question to hon. Minister of Agriculture was whether the land under cultivation is decreasing, for which my assessment was right, as the reply is that the land is decreasing. In the last four years, about 8 lakh hectares land under cultivation has decreased. Sir, apart from that, the average land holding has also

come down drastically. The current average land holding is 1.16 hectares, which is quite small. Now, with the result, the yield per hectare or the production per hectare has also gone down drastically.

I will give you two examples before I come to my main question. In the case of rice, the average yield in India is 2.4 tonnes per hectare, whereas in countries like China it is 4.7 tonnes; in Brazil it is 3.6 tonnes. On wheat, which is one of our main crops, the average yield in India per hectare is 3.15 tonnes versus South Africa, which produces 3.4 tonnes and China does 4.9 tonnes per hectare.

Now, with the abysmal level of yield per hectare, the agriculture is no more economically, probably, viable. We see a lot of farmers committing suicide.

My question to the hon. Minister is this. The land under cultivation is going down. The land average size holding is going down. The yield per hectare is going down. The farmers are committing suicide. Does the Government have a specific plan to address this problem?

कृषि और किसान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजीव कुमार बालियान): माननीय सभापति जी, 0.03 हैक्टेयर per year cultivable land कम हो रहा है, माननीय सदस्य की यह बात सही है। अगर आप productivity देखेंगे, तो over a period of time, productivity बढ़ी है, productivity कम नहीं हुई है। हो सकता है कि पिछले वर्ष सूखे की वजह से productivity में थोड़ी कमी रही हो, इसका कारण भी है। अगर आप किसी भी crop का average time period देखेंगे, तो हिन्दुस्तान में 80 से 110 दिन हैं। कुछ देशों में यह 180 से 200 दिन के करीब है। यह भी सही है कि देश में mechanism कम है, यह भी सच है कि fertilizers और quality seeds की कमी है। धीरे-धीरे इन पर काम तो जरूर हो रहा है, काम slow हुआ है, यह सच है, लेकिन यह कोई इतनी alarming situation नहीं है, आपने जो सबसे बड़ी बात कही है। अगर जमीन में थोड़ी बहुत कमी है, तो वह उसकी cropping intensity को बढ़ाकर दूर की जा सकती है। आज भी देश में cropping intensity मात्र 138 per cent है, जो कि बढ़कर 200 per cent तक जा सकती है। उसमें धीरे-धीरे progress भी है और उसमें सबसे बड़ा कारण irrigation की कमी है। उस पर focus भी है और 'प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना' द्वारा उस पर काम भी हो रहा है। इन्हीं सभी mechanisations के द्वारा भी काम बढ़ाया जा रहा है और quality seeds की सबसे बड़ी समस्या, आप कह सकते हैं कि पूरे भारत की रही है। हमेशा एक ही crop ली जाती रही है और उस crop को लेने का तरीका भी अलग ही रहा है। उसमें न pesticides का इस्तेमाल हुआ और न fertilizers का कभी पूरे भारत में रहा। सिंचाई सुविधाएं कम थीं, तो Green Revolution को पूरे भारत के लिए नई स्कीम शुरू की गई है, उसके द्वारा इसको address किया जा रहा है।

डा. कनवर दीप सिंह: सर, मैंने मंत्री जी से यह पूछा था कि अगर कोई specific plan है, तो मंत्री जी ने specific plan न बताकर केवल problems ही बताई हैं। But anyway that is the way it

is. Sir, the population in our country is increasing and the growth in agriculture is only two per cent. It accounts only for 14 per cent of our GDP. This, in my opinion, is an alarming situation which will reach probably those levels if we don't address it right away. We got independence in 1947. Almost that was the time when a country like Israel came into being. Israel does not have land for cultivation. Its soil is not good. They do not have water. I have had the privilege of visiting it. I come from agriculture background, so I went into the interiors and asked as to how they could do it. The simple slogan at that time was: One square inch of land and one drop of water should convert into one US dollar. And they did it. I think the time has come when we also need to address it. Otherwise, you will not be able to save the farmers; you will not be able to prevent them from committing suicides.

MR. CHAIRMAN: Question.

DR. KANWAR DEEP SINGH: In the reply, which the hon. Minister has given, he has only admitted the problems, which I have highlighted. They do exist. The time is to deploy the technology in agriculture. Do they have any specific plan for technology application in agriculture?

डा. संजीव कुमार बालियानः सर, मैंने जवाब दिया था कि देश में जो सबसे बड़ी समस्या है, वह irrigation की समस्या है। आज भी 45 per cent total irrigated land हमारे पास है। इसी समस्या को दूर करने के लिए मैंने आपसे 'प्रधान मंत्री कृषि योजना' का ज़िक्र किया था। जो Israel में हुआ है, वह drip irrigation, sprinkler, per drop, more crop, पानी की हर बूंद का इस्तेमाल, अगर कुछ प्रदेशों को छोड़ दिया जाए, तो आज तक यह हिन्दुस्तान में नहीं हुआ। इन प्रदेशों में तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात हैं। इन प्रदेशों में drip irrigation का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। ...**(व्यवधान)**...

श्री के.सी. त्यागीः Israel में कुछ और भी अच्छे काम हुए हैं।

डा. संजीव कुमार बालियानः यह सच है कि हम Israel से बहुत पीछे हैं और यह भी सच है कि अगर आप लगातार Israel में agriculture के field में investment देखेंगे, तो उसमें और हिन्दुस्तान में mechanisation को देखते हुए एक बहुत बड़ा gap है, और यह सच है कि agriculture का growth rate कम रहा है, 2 per cent से भी कम और यह basically इसीलिए है, अगर 55 per cent land देश का आज भी non-irrigated है, तो क्या यह कल्पना की जा सकती है कि लगातार दो सूखे के बावजूद हम growth rate ज्यादा ले जाएं? तो इसका तरीका यही है कि irrigation बढ़ाया जाए और यदि irrigation बढ़ेगा, तो हम सूखे का मुकाबला कर पाएंगे।

DR. KANWAR DEEP SINGH: My question is ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: That's all. ...*(Interruptions)*...

DR. SANJEEV KUMAR BALYAN: I answered it. ...*(Interruptions)*... There is the Scheme called Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. ...*(Interruptions)*... It is being implemented. इस वर्ष भी उसमें...

डा. कनवर दीप सिंहः सर....

MR. CHAIRMAN: Let there be a short question and a short answer.

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, माननीय सदस्य यदि योजना के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो फिर एक दिन सिंचाई योजना पर अलग से चर्चा करा लें, अच्छा रहेगा।

श्री शादी लाल बत्राः चेयरमैन सर, मैं मंत्री महोदय, से यह जानना चाहूंगा कि उन्होंने जो cultivated land बनाया है, वह total land का कितने percent है और barren land कितना है, land under forest कितना है, और क्या कोई ऐसी land है, जिसको हम cultivation के लायक बना सकें?

डा. संजीव कुमार बालियानः माननीय सभापति महोदय, देश का 328 मिलियन हेक्टेयर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। इसमें से आप कह सकते हैं कि, इस देश में 181.95 cultivable land मौजूद है। आप अंदाजन कह सकते हैं कि यह करीब 60 परसेंट है। हम जो ला सकते हैं, हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है, वह यह है कि हमारे पास जो current fallow land है, वह 15.82 million hectares लैंड है, जिसमें पिछले एक वर्ष से खेती नहीं हुई है। दूसरा लैंड fallow land होती है, other than current fallow, जिसमें पिछले पाँच सालों से खेती नहीं हुई है, वह भी देश के करीब 11 बिलियन हेक्टेयर मौजूद है। इस तरह से अगर इरिगेशन की फेसिलिटी बढ़े, तो 15.25 और 11, यानी की करीब 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड को एकदम से cultivable बनाया जा सकता है।

श्री बसवाराज पाटिलः माननीय सभापति जी, जब विश्व के अन्य देशों से तुलना करते हैं तो जो भारत की जमीन है, वह सबसे अधिक उपजाऊ जमीन है। यहाँ की जनसंख्या भी तीव्र गति से गढ़ रही है। कल यह भी हो सकता है कि दुनिया को अन्न देने की क्षमता भारत को लेनी पड़ेगी। ऐसे समय में हमारे पास अधिक cultivable लैंड का स्टॉक रखते हुए, उसको नॉन एग्रीकल्वरल लैंड में कंवर्ट करना, केवल देश के अन्न की समस्या नहीं, बल्कि दुनिया के अन्न की समस्या के लिए संकट बन सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में कृषि मंत्रालय क्या सोचता है?

डा. संजीव कुमार बालियानः माननीय उपसभापति महोदय, 2007 में "नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स" आई थी। उसी समय कृषिं मत्रालय द्वारा सभी प्रदेश सरकारों को एडवाइज़ दी गई थी कि एग्रीकल्वरल cultivable लैंड को नॉन एग्रीकल्वरल लैंड में मिनिमम ट्रांसफर किया जाए। अगर इंडस्ट्री भी लगानी है, कुछ और चीज़ है तो वेस्ट लैंड पर होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो cultivable लैंड है, कुछ ऐसी योजनाएं हैं, जैसे सड़कें, रेलवे, इरिगेशन फैसिलिटीज़, बिजली आदि, जिनमें कुछ न कुछ cultivable लैंड हमेशा ही कम होता जाएगा। आप प्रैक्टिकली उसे किसी भी तरह से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जो .03 मिलियन हेक्टेयर की कमी है, वह बहुत ज्यादा नहीं है। हम वेस्ट लैंड को कंवर्ट करके उसको रोक सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले बहुत सालों से हमारा नेट शोन एरिया लगभग वही है, कम नहीं है।

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः सभापति महोदय, हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। पहले घाघ की कहावत थी कि, "उत्तम खेती, मध्यम बान।" हमारा देश पूरी तरह से कृषि पर आधारित देश है। इस समय किसान अपनी कृषि छोड़कर बाहर पलायन कर रहा है, क्योंकि घाटे की खेती हो रही है। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या वे कम पानी की फसलें उगाने के लिए कोई ऐसा इंतजाम करेंगे, जिससे कि किसान को ज्यादा लाभकारी मूल्य मिले और किसान को खुद अपनी खेती का मूल्य निर्धारण करने का अधिकार मिले। केंद्र सरकार कम मूल्य निर्धारित करती है, इसलिए क्या आप किसान को भी उद्योगपतियों की तरह पावर देंगे, उन्हें यह अधिकार देंगे कि किसान अपनी फसल का मूल्य निर्धारित करे?

डा. संजीव कुमार बालियानः माननीय सभापति महोदय, किसान को अभी भी यह अधिकार है कि वह एमएसपी पर अपनी फसल न बेचे। ...(**व्यवधान**)...

श्री के.सी. त्यागीः नहीं है, यह गलत है।

डा. संजीव कुमार बालियानः नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, किसान को अधिकार है। अगर मार्किट में स्टॉक ज्यादा है, तो उस पर कोई कंडीशन नहीं है कि किसान को अपनी फसल एमएसपी पर बेचनी ही है। ...(**व्यवधान**)... वह अलग बात है। ...(**व्यवधान**)... आदरणीय सदस्य ने पूछा था कि क्या अधिकार है? माननीय सदस्य ने अधिकार की बात पूछी थी, वह अलग बात है कि एमएसपी पर बिक रहा है, लेकिन उन्होंने अधिकार की बात कही थी। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आज भी किसान को अधिकार है कि किसी भी तरफ, एमएसपी से ज्यादा अपनी फसल को बेच ले, यह अधिकार उसे प्राप्त है। ...(**व्यवधान**)...

श्री विशम्भर प्रसाद सिंहः देखिए, जिस तरह उद्योगपति अपने मूल्य का निर्धारण करता है, ...(**व्यवधान**)... उसी प्रकार किसान को अधिकार होना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. ...*(Interruptions)*... बैठ जाइए ...(**व्यवधान**)... Sit down. Thank you.

श्री भूपिंदर सिंहः सभापति जी ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. ...*(Interruptions)*... It is not your question, sit down. Why do you want to speak on every subject? Sit down, please. Has the question been answered?

Ongoing/pending railway projects in Maharashtra

*138.SHRI SANJAY RAUT: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the present status of ongoing/pending railway projects in Maharashtra, project-wise, on cost-sharing basis between Government of Maharashtra and the Ministry of Railways;

(b) whether Government of Maharashtra has proposed new railway lines/ construction works for balanced socio-economic development of the State on cost-sharing basis; and